दिल्ली, नोएडा, साहिबाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, मेरठ, हापुड़ से एक साथ प्रसारित

विशेष खबर

हर खबर की खबर

विशेष खबर
www.visheshkhabar.in

• वर्ष: • 2 अंक: 5
पृष्ठ : 8
गाजियाबाद
1 से 15 जुलाई-2019
मूल्य: 10 रुपये
पाक्षिक समाचार पत्र

visheshkhabarvk@gmail.com
RNI: UPHIN/2017/74151

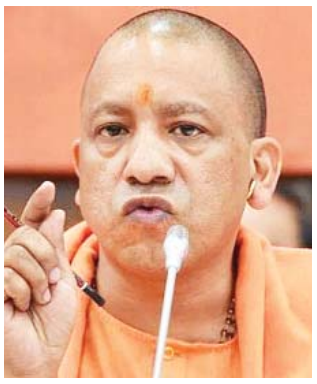

पेज-02 पलायन के दोषियों के साथ अफसरों को भी मिले सजा

अन्दर के पेजों पर
3 अध्यक्ष पद पर महिला अधिवक्ता के खड़े होने से दिलचस्प हुआ बार का चुनाव
4 बुलेटप्रूफ गाड़ी होती तो बच सकते थे कृष्णानंद राय
6 कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस चाहते हैं नए पुलिस कप्तान
7 सभी दलों में एक रोग बन गया है परिवारवाद
8 क्या अपनी रैंकिंग को बचा पाएगा गाजियाबाद नगर निगम?

Budget 2019

न्यू इंडिया का 'निर्मल बहीखाता'

- अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ा
- घर खरीद पर छूट अब 3.5 लाख
- प्राइवेट ट्रेनों का संचालन करेगा रेलवे
- महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
- उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़
- रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार पार्ट-2 का पहला केंद्रीय बजट 2019 पेश कर दिया है। बजट-2019 में तात्कालिक राहत से ज्यादा भविष्य के भारत और उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है। बजट में एक तरफ घर और इलेक्ट्रिक कार खरीदारी में छूट देकर मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाकर सरकार ने हिसाब बराबर कर लिया है। मतलब ये बजट 'एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले' की तर्ज पर तैयार किया है। दो घंटे 10 मिनट के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कई नई योजनाओं के एलान के साथ कई वस्तुओं के काम घटाने और बढ़ाने की घोषणा की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट से अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। वित्त मंत्री ने 5 करोड़ रुपये या उससे ऊपर की आय वाले अमीरों के लिए टैक्स पर लगने वाला सरचार्ज बढ़ा दिया है। इसके अलावा जिनकी आय 2 से 5 करोड़ के बीच है, उनको 3 फीसद का सरचार्ज देना होगा। 5 करोड़ से ऊपर की आय पर 7 फीसद का सरचार्ज देना होगा।

होम लोन लेने वालों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अगर आप होम लोन लेकर घर खरीदने की सोच रहे हैं या घर खरीद चुके हैं और उसकी एटक भर रहे हैं तो आपके लिए बजट अच्छी खबर लेकर आया है। होम लोन के ब्याज के पुनर्भुगतान पर पहले जहां सालाना 2 लाख तक की छूट मिलती थी, उसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

रेलवे में निजी भागीदारी के साथ सरकार देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रेलवे की योजना है कि निजी भागीदारों को पर्यटन वाले रूट पर कुछ चुनिंदा ट्रेनें संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही 22 स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारे केंद्र बिंदु हैं। हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला परियोजना के जरिए हम देश के हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवीन ऊर्जा का निजी उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। गांव में स्वच्छ भारत अभियान का काफी प्रभाव देखने को मिला है। लगभग 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। इनमें से 45 हजार शौचालय गूगल मैप पर हैं। अन्नदाता को ऊजार्दाता बनाने के लिए कई प्रोग्राम हैं।

वित्तमंत्री ने बजट 2019 में महिलाओं के लिए कई घोषणाएं का हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ, मुद्र योजना के तहत महिलाओं को सस्ता लोन देने का एलान किया गया है। महिला उद्यमियों को अब एक लाख तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही जन धन खाते वाले प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) सदस्य, 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी गई है। साथ ही कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाना हमारी सरकार का लक्ष्य है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि अब हर गांव में स्वच्छ भारत अभियान को सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरह से काम करेगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश हर हिस्से को प्रभावित किया है। मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लिए भी नए बदलाव करने जा रही है। सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ की राशि खर्च करेगी। सीतारमण ने कहा कि दुनिया के 200 टॉप कॉलेजों में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज ही शामिल हैं। ऐसे में केंद्र सरकार इन कॉलेजो की संख्या बढ़ाने के लिए नए प्रयास करेगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खेलों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जाएगा। खिलाड़ियों के विकास के लिए इसे खेलो इंडिया के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने टॉप संस्थानों को 400 करोड़ देने की बात भी कही। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में डिजिटल इंडिया पर खासा जोर दिया है। बजट भाषण की शुरूआत में ही उन्होंने डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में इंटरनेट सेवा देने के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट था जिसे पीयूष गोयल ने पेश किया था।

बजट पर प्रतिक्रिया पेज 5 पर

इनकी बढ़ी कीमतें

बजट में पेट्रोल, डीजल और सोने के साथ आयातित किताबों पर पांच प्रतिशत का शुल्क बढ़ाया है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स सिंथेटिर रबर, पीवीसी और टाइल्स की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही, तंबाकू उत्पादों पर भी शुल्क बढ़ाया गया है, जिसके बाद उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही, सोने के अलावा चांदी और चांदी के आभूषणों पर भी लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। वहीं बजट 2019 में ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उत्पाद, मूल धातु के फिटिंग्स, फ्रेम और सामान, एयर कंडीशनर, लाउडस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, सिगरेट आदि की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

ये हुए सस्ते

इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर जीएसटी की दरों को घटा कर 12 से 5 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने में लिये गए लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। साथ ही बजट में होम लोन सस्ते होंगे। सरकार 45 लाख तक के घर पर साढ़े तीन लाख रुपये की छूट देगी। वहीं साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, डिटरजेंट वाशिंग पाउडर, बिजली का घरेलू सामानों पंखे, लैम्प, ब्रीफकेस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों के अलावा गद्दा, बिस्तर, चश्मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्ता, मियोनीज, धूपबत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन, ऊन और ऊनी धागों की कीमतों में कटौती की गई है, जिसके बाद इन्हें खरीदना और सस्ता हो जाएगा

वित्त मंत्री ने बजट नहीं बही खाता पेश किया

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को संसद में प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परंपरा तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह एक फोल्डर में बजट रखा था। अब तक वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में ही बजट लेकर संसद पहुंचते थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने फोल्डर में बजट ले जाने पर कहा कि यह सच्ची भारतीय परंपरा है। यह पश्चिमी मानसिकता की गुलामी से बाहर आने का प्रतीक है। इसे आप बजट नहीं बल्कि बही खाता कह सकते हैं।

संपादकीय

पलायन के दोषियों के साथ अफसरों को भी मिले सजा

विनीतकांत पाराशर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले को खुद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अफसरों से गोपनीय रिपोर्ट तलब की है। एक अहम सवाल है कि अस्सी फीसदी हिंदू अपने ही देश में पलायन को बाध्य क्यों होते हैं।

हिंदू परिवारों के पलायन का मसला एक बार फिर यूपी में सियासत और मीडिया की सुर्खियां बना है। लेकिन इस बार नाम के साथ स्थान भी परिवर्तित है। अबकी कैराना नहीं मेरठ का प्रहलाद नगर है। हालांकि सारे हालात तीन साल पूर्व कैराना जैसे ही हैं। पलायन की खबर से राज्य की योगी सरकार की नींद उड़ गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले को खुद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अफसरों से गोपनीय रिपोर्ट तलब की है। एक अहम सवाल है कि अस्सी फीसदी हिंदू अपने ही देश में पलायन को बाध्य क्यों होते हैं। इसके अलावा पलायन की बात यूपी ही से क्यों उठती हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब हिंदू परिवारों के पलायन की बात सामने आ रही है। कैराना से जब पलायन का मसला उठा था तो राज्य में उस दौरान अखिलेश यादव की सरकार थी। लेकिन इस बार हिंदुत्व की हिमायती भाजपा के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जिसकी वजह से सरकार पलायन के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। कैराना और मेरठ से पलायन की जो स्थिति बनी है उसमें काफी समानता है। तीन साल पूर्व कैराना में जब पलायन का मसला उठा था तो उस वक्त भी जून का महीना था। भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। जिसकी वजह से यह मसला अखिलेश सरकार की गले की फांस बन गया था। लेकिन अब वहीं बात योगी को मुश्किल में डाल दिया है कि आखिर हिंदू परिवारों का पलाया कैसे हो रहा है या फिर पलायन की खबरों का सच क्या है। कैराना मसले पर मानवाधिकार आयोग ने तत्कालीन सरकार से रिपोर्ट भी तलब किया था।

प्रश्न उठता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम विभाजन की बात क्यों करते हैं। भारत में लाखों की संख्या में रोहिंग्या और बंग्लादेशी बेधड़क निवास कर

सकते हैं तो हमें आपस में रहने और एक दूसरे के धर्म संस्कृति से क्यों इतनी घृणा है। पलायन का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही क्यों उठता है। जबकि पूर्वी यूपी इस तरह की बातें सामने नहीं आती हैं। हिंदूओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे भी पश्चिमी यूपी में अधिक होते हैं। यह राष्ट्रीय; एकता और अखंड़ता के लिए बड़ा खतरा है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के मेरठ के प्रहलाद नगर से 125 से अधिक हिंदू परिवारों के पलायन हुआ है। आरोपों में कितना दम है यह जाँच का विषय है। मीडिया रपट में कहा गया हैं कि वहां कई मकानों पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। यह तस्वीर ठीक उसी तरह है जैसे कैराना की थी। पलायन किसी के लिए बेहद पीड़ादायक है। अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी होती है। कोई इतनी आसानी से बसी बसायी गृहस्थी नहीं छोड़ना चाहता है। जब पानी नाक से बाहर होने लगता है तभी इस तरह कदम उठाए जाते हैं। अपने ही देश में पलायन को मजबूर होना किसी अभिशाप से कम नहीं। कश्मीरी पंड़ित खूबसूरत बादी को छोडकर क्यों पलायित हुए। क्या यही सच कैराना के बाद अब मेरठ का है। आरोप है कि वहां समुदाय विशेष के युवक खुले आम गुंड़ागर्दी करते हैं। महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। मोबाइल, चेनस्नेचिंग और बाइक स्टंग कर हिंदू परिवारों की महिलाओं को परेशान करते हैं। भद्दी गालियां देते हैं। जिसकी वजह से हिंदू परिवारों का जीना दुश्वार हो गया है। घर के लोग लड़कियों को अकेले स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं। जिसकी वजह से पीड़ित हिंदू परिवार मेरठ के प्रहलाद नगर से पलायित होकर दूसरी जगह आशियाना तलाश रहे हैं। अब तक काफी लोग पलायित भी हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह के हालाता सिर्फ प्रहलादनगर का नहीं बल्कि स्टेट बैंक कालोनी, रामनगर, विकासपुरी, हरिनगर कालोनियों का भी है। मेरठ अब सियासी मुद्दा भी बनता दिखता है।

भाजपा ने लव जिहाद की तर्ज पर इसे लैंड जिहाद का नाम दिया है। जिसकी वजह से यह मसला गरमा सकता है। लेकिन यह राजनीति का विषय नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या जहां समुदाय विशेष के लोगों की आबादी अधिक होगी वहां दूसरे समुदाय यानी कम आबादी या संख्या वाले लोग नहीं रह पाएंगे। इस तरह की संस्कृति हम क्यों विकसित करना चाहते हैं। हम जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत क्यों चरितार्थ कर रहे हैं। समुदाय के नाम पर नंगा नाच क्यों किया जा रहा है। महिलाओं और बेटियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। योगी सरकार इस पर खुद गंभीर है। जांच के बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो दोषी लोगों के साथ जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसकी वजह से पलायन जैसे शर्मनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाले मसले फिर कभी हमारी बहस के मसले न बन पाएं।

अच्छा खाएं-स्वस्थ रहे
आइडिया मसालों के संग

सुनहरा अवसर: अब आइडिया मसालों के साथ व्यापार करके कमाएं लाखों रूपये महीना।
विभिन्न जिलों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए
सम्पर्क करें: 9654008835

अध्यक्ष पद पर महिला अधिवक्ता के खड़े होने से दिलचस्प हुआ बार का चुनाव

अध्यक्ष के लिए मैदान में चार उम्मीदवार, मतदाताओं को रिझाने की हर संभव कोशिश

गाजियाबाद। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में वकीलों को सीओपी नंबर पर ही मतदान करने के निर्णय से इस बार अब तक सीओपी नंबर वाले 1512 अधिवक्ताओं की सूची चस्पा की गयी है। करीब 150 अधिवक्ताओं के वोट देने को लेकर एल्डर कमेटी को निर्णय लेना है। अध्यक्ष पद पर चार उम्मीदवारों के बीच जंग छिड़ गयी है। इसमें पहली बार महिला उम्मीदवार धर्मशिला के आने से चुनाव रोचक हो गया है।

अध्यक्ष पद के लिए सुनील दत्त त्यागी, नाहर सिंह यादव, सुरेंद्र चौधरी और धर्मशिला चुनाव मैदान में डटे हुए है। कुल पांच पदों के लिए 30 उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। बार एसोसिएशन गाजियाबाद के चुनाव में पहली बार यूपी बार काउंसिल के तहत एल्डर कमेटी की ओर से सीओपी नंबर पर मतदान देने की प्रक्रिया ने वकीलों के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी है। अब तक इस निर्णय के तहत गुरुवार को कमेटी की ओर से 1512 अधिवक्ताओं के नाम सूचीबद्ध किए गए। चुनाव प्रभारी अनिल पंडित ने बताया कि एल्डर कमेटी के चेयरमैन रविदत्त त्यागी के समक्ष 150 अधिवक्ताओं के मतदान के लिए आवेदन आये हैं। जिन्होंने सीओपी नंबर (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर) के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया को किया है। उस पर कमेटी निर्णय लेगी। नामांकन वापिसी वाले दिन अध्यक्ष पद पर पर्चा भरने वालों में किसी उम्मीदवार ने पर्चा वापिस नही लिया। चार उम्मीदवारों में सुरेंद्र चौधरी, सुनीलदत्त त्यागी उर्फ भगत जी, पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव व महिला अधिवक्ता धर्मशिला की ओर से चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। 11 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी मैदान मे उतरे इन उम्मीदवारों ने वकीलों को चैम्बर दिलाने का मुद्दा ही प्रमुखता से उठा रखा है। साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था, पार्किंग, सौंदर्यीकरण से लेकर वातानूकूलित डिजिटल लायब्रेरी, वाटर कूलर व शौचालय की व्यवस्था क राने का दावा कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बार के अध्यक्ष पद के पहली बार उतरी महिला अधिवक्ता धर्मशिला ने चुनाव को रोचक बना दिया है। उनके चुनाव में कूदने से इस बार महिला वोटों के कटने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस बार का चुनाव पहले के चुनावों के मुकाबले काफी दिलचस्प माना जा रहा है।

विजयनगर में पांच घंटे तक होगी बिजली कटौती

एक सप्ताह तक दिन-रात में होगी रोस्टिंग

गाजियाबाद (विशेष खबर)। एनएच-24 पर चले रहे चौड़ीकरण और विजयनगर क्षेत्र में ओवर लोडिंग की परेशानी को देखते हुए बिजली विभाग ने एक सप्ताह तक दिन और रात में पांच घंटे की रोस्टिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारियों की ओर से रोस्टिंग चार्ट भी जारी कर दिया गया है।

विद्युत निगम जोन तीन के अधिशासी अभियंता की ओर से जारी रोस्टिंग शेड्यूल के अनुसार 4 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रतिदिन दिन में पांच घंटे और रात में पांच घंटे कटौती की जाएगी।

इस रोस्टिंग से आम उपभोगताओं को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए रोस्टिंग अलग-अलग एरिया में होगी। इस रोस्टिंग से लाइन पार विजयनगर क्षेत्र की 50 से ज्यादा कॉलोनियां प्रभावित रहेंगी। 10 घंटे की कटौती 5 सब स्टेशनों के तहत आने वाली कॉलोनियों में अलग-अलग समय पर होगी। इस कटौती को प्रति सब स्टेशन एक घंटा रखा गया है।

कहां पर कब गुल होगी बिजली

- प्रताप विहार सब स्टेशन से जुड़े इलाके में दोपहर में 12 से 1 बजे तक और रात में 8 से 9 बजे तक कटौती होगी
- इलेक्ट्रो स्टील सब स्टेशन पर दिन में एक बजे से 2 बजे तक और रात में 9 से 10 बजे तक
- एसएसजीटी सब स्टेशन पर दिन में 2 से 3 बजे तक और रात में 10 से 11 बजे तक
- अकबरपुर सब स्टेशन पर दिन में 3 से 4 बजे और रात में 11 से 12 बजे तक
- क्रॉसिंग सब स्टेशन पर दिन में 4 से 5 बजे तक और रात में 12 से 1 बजे तक रोस्टिंग रहेगी।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा तेज

गाजियाबाद। जीडीए ने राजनगर एक्सटेंशन में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम को बनाने के लिए आने वाली बाधा को शीघ्र ही दूर करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश मिश्रा ने जीडीए तहसीलदार के साथ उपाध्यक्ष से मुलाकात की। जीडीए उपाध्यक्ष ने शीघ्र ही इस मैटर को सुलझाने का वायदा किया है। उन्होंने वीसी से स्टेडियम के सामने की सड़क का निर्माण शीघ्र कराने का आश्वासन दिया और आवश्यक भूमि का लैंड यूज चेंज करने के लिए शासन को भेजने की बात की। जीडीए वीसी ने आश्वासन दिया कि सड़क की सीमा जल्द चिह्नित कर दी जाएगी।

राजनगर एक्सटेंशन मोरटी गांव में यूपीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 33.54 एकड़ भूमि खरीद रखी है। अतिरिक्त तल क्षेत्र (एफएआर) की उलझन को कम करने के लिए स्टेडियम के दो मानचित्र पास कराए जाएंगे। क्रिकेट ग्राउंड का मानचित्र 0.40 एफएआर के हिसाब से बनाया जाएगा। कमर्शियल, एकेडमी, होटल और आवास बनाने के लिए अलग मानचित्र प्रस्तुत करेंगे।

इस पर ज्यादा एफएआर की मांग की जाएगी। अधिकतम 2.4 एफएआर अनुमन्य होगा। मास्टर प्लान में स्टेडियम की जमीन का वर्तमान भू-उपयोग कृषि है। यूपीएसए ने

मिश्रित भू-उपयोग की मांग की थी। जिससे वहां स्टेडियम के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, एकेडमी और अन्य व्यवसायिक गतिविधियां की जा सकें। भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी। इसके लिए जीडीए ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्टेडियम के लिए खरीदी गई भूमि के बीच से बिजली की दो हाइटेंशन लाइन (एचटी) जा रही हैं। उनको शिफ्ट करने की मांग यूपीसीए की तरफ से रखी गई थी। शहर हित और निवेश के नजरिए से स्टेडियम को महत्वपूर्ण बताते हुए शासन ने विद्युत निगम को लाइन शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में जीसीए के चेयरमैन राकेश मिश्रा का कहना है कि जीडीए उपाध्यक्ष ने इस दिशा में तेजी से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जल्द ही सभी प्रक्रिया पूरी करके स्टेडियम का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

बुलेटप्रूफ गाड़ी होती तो बच सकते थे

कृष्णानंद राय

हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत 5 आरोपी बरी

नई दिल्ली। बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समेत 5 आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया है। यूपी के गाजीपुर की मुहम्मदाबाद विधानसभा सीट से तत्कालीन बीजेपी विधायक राय को 29 नवंबर 2005 को उस वक्त गोलियों से भून दिया गया था, जब वह सियारी नाम के गांव में एक क्रिकेट टूर्नमेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे।

राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। हमेशा बुलेटप्रूफ गाड़ी से चलने वाले राय उस दिन बुलेटप्रूफ गाड़ी में नहीं थी। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर लगा था। मुन्ना बजरंगी की कुछ साल पहले जेल में हत्या हो गई थी। कोर्ट ने अंसारी और मुन्ना बजरंगी समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था।

कृष्णानंद राय के भाई रामनारायण राय ने कोर्ट में बयान दिया था कि 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के सियारी गांव में क्रिकेट टूनार्मेंट का उद्घाटन करने के बाद राय अपने गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना यादव, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह के साथ कनुवान गांव की ओर जा रहे थे। राम नारायण राय के मुताबिक वह खुद दूसरे लोगों के साथ एमएलए की गाड़ी से पीछे चल रही गाड़ी में सवार थे। बासनिया छत्ती गांव से डेढ़ किलोमीटर आगे जाने पर सिल्वर ग्रे कलर कर टाटा सूमो सामने से आती हुई नजर आई। सूमो से निकले सात-आठ लोगों ने एमएलए की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस गाड़ी में सवार सातों लोग मारे गए।

राम नारायण राय ने कोर्ट में बताया था कि फायरिंग के दौरान हमलावर बोल रहे थे कि 'मारो इसे, अफजाल भाई और मुख्तार भाई को बहुत तंग कर रखा है'। राय के मुताबिक हत्याकांड के बाद हमलावरों ने एमएलए की चोटी भी काटी थी। राय ने यह भी बयान दिया कि फायरिंग मुन्ना बजरंगी उर्फ प्रेम प्रकाश सिंह, अता उर रहमान उर्फ बाबू, एजाज उल हक, फिरदौस और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा ने की थी।

सटीक मुखबिरी के चलते गई जान

गाजीपुर जिले के करीमुद्दीनपुर क्षाना क्षेत्र के गोडउर निवासी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मुख्तार गैंग के हमले की आशंका के चलते काफी समय से बुलेटप्रूफ गाड़ी से चलते रहे। वारदात के दिन वह पास के सियारी गांव में एक क्रिकेट टूर्नमेंट का उद?घाटन करने जाते समय बुलेटप्रूफ गाड़ी घर पर ही छोड़ गए थे। बुलेटप्रूफ गाड़ी का प्रयोग न किए जाने की जानकारी मुखबिर के जरिए हमलवारों तक पहुंची तो घटना को अंजाम देने का मौका मिल गया। वापस घर लौटते समय कृष्णानंद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं।

दो गवाहों की संदिग्ध मौत से फायदा

उस दिन हत्याकांड में शशिकांत राय नाम के एक घायल, जो कि उस गाड़ी में ही घायल पड़े हुए थे, लेकिन बाद में जिंदा बच गए थे। वह एक महत्वपूर्ण गवाह थे और जहां घटनाक्रम हुआ था, वहां खेत में एक मनोज गौड़ नाम का व्यक्ति काम कर रहा था। इन दोनों लोगों की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इनकी भी गवाही नहीं हो सकी, जिसके चलते इस केस में अंसारी बंधुओं को काफी फायदा पहुंचा। हत्याकांड के चश्मदीद कृष्णानंद के भाई रामनारायण राय ने अपनी गवाही में अदालत को बताया था कि किसी भी आरोपी ने कभी यह नहीं कहा कि उसने वारदात को अंजाम नहीं दिया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मामले का ट्रायल दिल्ली की कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। आरोपी एजाजुल हक की तरफ से कोर्ट में ऐडवोकेट आरएस मलिक ने दलील दी थी कि उनका मुवक्किल शारीरिक रूप से अक्षम है और अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता। वह वारदात में इस्तेमाल एके-47, एके-56 या 7.62 एसएलआर जैसे हथियार कैसे चला सकता है। अदालत ने इस गवाही को स्वीकार किया था।

कृष्णानंद राय हत्याकांड में कब-क्या हुआ?

- 29 नवंबर 2005- गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को गोलियों से भून दिया गया। कृष्णानंद राय पर 500 राउंड फायरिंग हुई थी। इस हमले में एके-47 का इस्तेमाल हुआ।
- 21 फरवरी 2006- बीजेपी विधायक हत्याकांड में यूपी पुलिस की तरफ से पहली चार्जशीट फाइल हुई। इसमें एजाजुल हक, अफजाल अंसारी, प्रेमप्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी, अताउर्रहमान और फिरदौस का नाम शामिल।
- 15 मार्च 2006- यूपी पुलिस ने इस मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की। इसमें मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया।
- मई 2006- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक हत्याकांड की सीबीआई जांच का आदेश दिया। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर फैसला।
- 30 अगस्त 2006- सीबीआई ने हत्याकांड में तीसरी चार्जशीट फाइल की, इसमें संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को भी आरोपी बनाया।
- 12 दिसंबर 2006- सीबीआई ने चौथी चार्जशीट फाइल करते हुए राकेश पाण्डेय व रामू मल्लाह को भी आरोपी बनाया।
- 20 मई 2007- सीबीआई ने पांचवीं चार्जशीट दाखिल करते हुए बाहबुली विधायक मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया।
- 22 अप्रैल 2013-सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड की गाजीपुर जिला अदालत में चल रही सुनवाई को सेशंस कोर्ट दिल्ली में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया।
- 15 मार्च 2014- सीबीआई ने कृष्णानंद हत्याकांड में छठीं चार्जशीट प्रेमप्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी के खिलाफ दाखिल की।
- 22 मई 2019- सीबीआई कोर्ट ने इस हत्याकांड में फैसले को सुरक्षित रखा।
- 3 जुलाई 2019-गवाहों के मुकरने के बाद सीबीआई अदालत ने मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों को इस हत्याकांड के आरोप से मुक्त कर दिया।

पार्षद रेखा दीक्षित ने सुनी साउथ अनारकली कालोनी की समस्याएं

निरीक्षण के बाद तुरंत कराया समस्याओं का निदान

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्ड 22 ई की पार्षद रेखा दीक्षित द्वारा साउथ अनारकली कालोनी में सफाई अभियान चलाया गया। जिसमें निगम पार्षद रेखा दीक्षित ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। पार्षद ने क्षेत्रीय नागरिकों से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के बारे में पूछा और सम्बंधित अधिकारियो को सफाई व्यस्था दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए। सफाई अभियान के दौरान नाली की पुलिया का मैन होल टुटा हुआ पाया गया तो पार्षद ने वर्क्स विभाग के जेई देव स्वरुप सिंह को निर्देश देकर नया मैन होल लगवाया। जिसका क्षेत्रीय आरडब्ल्यूए के नागरिको ने निगम पार्षद का धन्यवाद किया। इस मौके पर निगम से सफाई निरीक्षक परविंदर शर्मा, मलेरिया निरीक्षक भूले राम शर्मा व आरडब्ल्यूए प्रधान अनिल गोयल, विजय मित्तल, प्रवीण गुप्ता, संजीव भाटिया, कमल पोपली, भारत भूषण, सतीश भारद्वाज, अनारकली मंडल अध्यक्ष राकेश गुप्ता, मंजू गुप्ता, रितु चौधरी, उमा खन्ना, सोनिया, मुस्कान अग्रवाल, विकास गुलाटी, कुलदीप सिंह, मनोज शर्मा, पुनीत अरोड़ा, राकेश दीक्षित, देव ऋषि त्रिपाठी, दीपक कपूर, पुनीत शर्मा, अनिल गर्ग, प्रवेश सिंघल, सुनील शर्मा, राजन, कैलाश शर्मा, आदि कार्येकर्ता मौजूद रहे।

एक मुलाकात

नई दिल्ली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी से विशेष खबर के प्रधान संपादक विनीत कांत पराशर ने मुलाकात की और उनकी बड़ी जीत पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान दोनों के बीच राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से दूसरी बार सांसद चुने गए है और इस बार उनकी जीत 5.67 लाख मतों से हुई है।

सीएनजी दामों से मुश्किल में वाहन चालक

15 दिन में सात बार बढ़े सीएनजी के रेट

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते जा रहे सीएनजी के दामों से वाहन चालकों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। बुधवार से एक रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दिए गए हैं। पिछले 15 महीनों में सीएनजी के दाम में यह सातवीं बढ़ोतरी है। दिल्ली में सीएनजी के दाम 90 पैसे बढ़कर 46.60 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में एक रुपये बढ़कर 52.95 रुपये प्रति किलो हो गए। इसी प्रकार, हरियाणा में रेवाड़ी, गुरुग्राम और करनाल में सीएनजी की कीमत में 95 पैसे की वृद्धि की गई है। गुरुग्राम और रेवाड़ी में सीएनजी की कीमत 58.45 रुपये प्रति किलोग्राम होगी कि करनाल में 55.45 रुपये होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों को सीएनजी की आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने एक वक्तव्य में कहा है कि यह वृद्धि गैस पाइपलाइन पारेषण शुल्क में हालिया बदलाव के कारण हुई है। अप्रैल 2018 के बाद से अब तक सात बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। प्राकृतिक गैस की कीमतों में तेजी और रुपये में गिरावट के चलते पिछले महीने अप्रैल में एक रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी। अप्रैल 2018 से सीएनजी के दाम में 6.89 रुपये प्रति किलोग्राम तक की वृद्धि की गई है। हालांकि, आईजीएल ने खाना बनाने में इस्तेमाल पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) के दाम में वृद्धि नहीं की है। स्थानीय करों के प्रभाव से सीएनजी और पीएनजी के दाम अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है।

इंद्रप्रस्थ गैस ने कहा कि वह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में चुनिंदा आउटलेट पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सीएनजी की दाम में 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट की पेशकश जारी रखेगी। इस दौरान, दिल्ली में सीएनजी 45.10 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 51.45 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिलेगी।

एक मुलाकात

नई दिल्ली। तेजतर्रार और मृदुभाषी महेंद्र कुमार मिश्रा को प्रीत विहार दिल्ली थाने का एसएचओ बनाए जाने पर विशेष खबर के प्रधान संपादक विनीत कांत पराशर उनसे मुलाकात की और उन्हें थाने का कार्यभार संभालने पर बधाई दी। प्रधान संपादक ने एसएचओ को भेंट स्वरूप गाय का समृति चिन्ह सौंपा। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले 1995 बैच के पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार मिश्रा बेहद सीधे और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्हें स्पेशल ब्रांच से यहां पर भेजा गया है। महेंद्र मिश्रा की गिनती उन तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों में होती है, जिन्हें अपराध नियंत्रण के लिए प्लानिमग के तहत भेजा जाता है। इससे पहले वह कई थानों में एसएचओ रह चुके है।

'नई बोतल में पुरानी शराब' जैसा बजट-2019!

संवाददाता

नई दिल्ली। मोदी सरकार पार्ट-2 के इस बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। सत्ता पक्ष जहां बजट को न्यू इंडिया का बजट करार दा है। वहीं विपक्ष ने बजट को नई बोतल में पुरानी शराब की संज्ञा दी है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई योजना नहीं दी है। साथ ही इस बजट में धन्नासेठों को तरजीह दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह न्यू इंडिया का बजट है जिसमें देश के कृषि क्षेत्र को बदलने का रोडमैप है। यह उम्मीदों का बजट है। पीएम मोदी ने कहा यह देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा, युवका को बेहतर कल मिलेगा।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इंडिया का बजट पेश किया जो एक समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रख रहा है, जिसके उदय में 130 करोड़ भारतीयों की मेहनत है। यह बजट भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सपने पूरा करने के लिए पंख देता है।

उन्होंने कहा कि बजट में स्पष्ट रूप से भारत के विकास के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दशार्या गया है, जहां किसान समृद्ध होगा, गरीब सम्मान की जिंदगी जीएगा, मध्यम वर्ग को अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और भारतीय उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। यह वास्तव में आशा और सशक्तिकरण का बजट है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाकर यह एक भविष्य का बजट है। यह भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में ले जाने में कामयाब होगा। इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वह गरीब, पिछड़े या अमीर हों।'

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'हमने पिछले 5 वर्षों में पहले ही अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जब हम अब फिर से 5 साल पूरे करेंगे, तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था होंगे।'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'यह एक दूरदर्शी बजट है, वृहद आर्थिक स्तर पर, कोई भी कह सकता है कि, यह भारत को 5 ट्रिलियन डॉलक की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम के सपने की घोषणा है। बजट का लक्ष्य 'गांव, गरीब और किसान' को बदलना है।

बजट पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'यह आजादी के बाद पहली बार है कि किसी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया है। मैं उसे बधाई देना चाहता हूं। बजट देश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करता है।'

धन्नासेठों की ही मदद करने वाला बजट : मायावती

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा, 'यह बजट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर कुछ बड़े–बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों की ही हर प्रकार से मदद करने वाला है, जिससे दलितों व पिछड़ों के आरक्षण की ही नहीं बल्कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान व ग्रामीण समस्या और भी जटिल होगी। देश में पूंजी का विकास भी इससे संभव नहीं है।' बीजेपी की केन्द्र सरकार द्वारा बजट को हर मामले में व हर स्तर पर लुभावना बनाने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन देखना है कि इनका यह बजट जमीनी हकीकत में देश की आमजनता के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होता है जबकि पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी, बदतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा से पीड़ित व परेशान है। यह बजट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर कुछ बड़े–बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों की ही हर प्रकार से मदद करने वाला है, जिससे दलितों व पिछड़ों के आरक्षण की ही नहीं बल्कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान व ग्रामीण समस्या और भी जटिल होगी। देश में पूंजी का विकास भी इससे संभव नहीं है।

पुराने वादों की दोहराया गया : अधीर रंजन

लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बजट में नया कुछ नहीं। पुराने वादों की दोहराया गया है। वे नए भारत के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यह बजट सिर्फ एक नई बोतल में पुरानी शराब है। कोई नई बात नहीं है, रोजगार पैदा करने की कोई योजना नहीं है, कोई नई पहल नहीं है।

कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस चाहते हैं नए पुलिस कप्तान

- चार्ज लेते ही एक्शन में दिखे पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह
- एसएसपी ने किया आते ही बाजार का निरीक्षण

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के नए पुलिस कप्तान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चार्ज संभालते ही पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह एक्शन में नजर आए। उन्होंने शहर के सबसे व्यस्त बाजारों का निरीक्षण किया और सुरक्षा का जायजा लिया। गाजियाबाद को लेकर नए कप्तान की क्या योजना है और सुरक्षा की दृष्टि से वह क्या नए प्रयोग करने पर विचार कर रहे है, इसी मुद्दे पर हमने नए कप्तान से चर्चा की।

साइबर सेल को करेंगे मजबूत

उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में साइबर क्राइम और स्थानों से कहीं अधिक है, इसलिए उनकी प्राथमिकता साइबर सेल को और अधिक हाईटैक बनाने की होगी। सिंह ने कहा कि मुजफ्फनगर और गाजियाबाद में घटित आपराधिक मामलों में कई अंतर हैं। जहां मुजफ्फरनगर में जघन्य अपराध व साम्प्रदायिक मामलों से जुड़ी घटनाएं अधिक हैं, वहीं गाजियाबाद में ठगी, धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के अधिक मामले होते हैं। उन्होंने कहा कि शासन के आदेश का अनुपालन करते हुए सरकार की नीतियों को लागू कराना, उनका प्रथम उद्देश्य रहेगा। इन नीतियों में बाल अपराध, महिला अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाना और घटित हो जाने पर उनका शीघ्र खुलासा करना उनका पहला कर्तव्य रहेगा।

अपराधियों की असली जगह सलाखों के पीछे

एसएसपी ने कहा कि अपराधियों की असली जगह जेल की सलाखें है और अपराध नियंत्रण के लिए उन्हें सीखचों के पीछे पहुंचाया जाएगा। सिंह ने कहा कि अपराध पर अंकुश पाने के लिए डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने जो कार्यशैली अपनाई थी, वह भी उसका अनुशरण करेंगे। एसएसपी ने कहा कि जो बदमाश गोली चलाएगा उसे जवाब भी गोली से दिया जाएगा। अपराध के खात्मे के लिए अपराधियों के खिलाफ सटीक व निरंतर अभियान चलाए जाएंगे। चोरी, छिनैती, लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी, डकैती, रेप और छेड़छाड़ के मामलों को रोकने के लिए पुलिस अब पहले से भी अधिक एक्टिव दिखाई देगी। सिंह का यह भी कहना है कि संगठित अपराध को भी ध्वस्त करने के लिए गंभीरतापूर्वक मुहिम चलाई जाएगी। पुलिस और जनता के बीच अधिक तालमेल बैठाने के लिए कम्युनिकेशन व कोर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा।

तेजतर्रार अफसरों में गिने जाते है सुधीर कुमार सिंह

एसएसपी सुधीर कुमार सिंह की गिनती तेजतर्रार आईपीएस अफसरों में होती है। सुधीर कुमार सिंह यहां आने से पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर थे। मुजफ्फरनगर अति संवेदनशहल जिला माना जाता है और अपराध के मामले में भी काफी चर्चित है। लेकिन सुधीर कुमार के तैनात होने के बाद कई कुख्यात अपराधी गोली का शिकार बने। सुधीर कुमार सिंह गाजियाबाद में भी पहले पुलिस उपाधीक्षक पद पर तैनात रह चुके हैं। सुधीर कुमार सिंह एएसपी हापुड़ भी रहे और वहीं से उनको प्रमोशन मिला। इसके बाद वो मेरठ में एसपी (आर), एसपी (ट्रैफिक) गोंडा सहित कई जनपदों में पुलिस कप्तान रहे। शासन ने उनको मुजफ्फरनगर जैसे संवेदनशील जिले की कमान सौंपी थी। वो बहुत ही अनुभवी एवं पुलिस विभाग में भी लोकप्रिय रहे। वो फैसला लेने काफी दबंग माने जाते हैं। इतना ही नहीं अपनी बेबाक और साफ छवि की वजह से कहीं भी कोई दंगा आदि होता है तो उनको बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी वर्किंग पर लोगों को भरोसा होता है।

अपराध बढ़ने पर थानेदार होंगे जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि दोपहर में एक से चार बजे तक वीआईपी कॉलोनियों और सोसायटी में विशेष रूप से पुलिस की गश्त रहेगी। जिन क्षेत्रों में दिन में चोरी होगी। उसके लिए संबंधित क्षेत्र के थानेदार जिम्मेदार होंगे। लंबित पड़े मामलों को प्रमुखता से निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में अपराध रोकना पहली प्राथमिकता है। प्रत्येक थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी रहेगी कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में वीआईपी व चोरी होने वाले क्षेत्रों में दिन में ही गश्त बढ़ाएं। दिन हो या रात चोरी की घटनाएं बढ़नी नहीं चाहिए। कहा कि लंबित पड़ी घटनाओं के खुलासे पर जोर रहेगा। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस बरतने की बात कही।

महिला अपराध पर रहेगी विशेष नजर

एसएसपी ने कहा कि जिले में महिलाओं पर हो रहे अपराध पर विशेष नजर रहेगी। चेन स्नेचिंग, छेड़छाड़ और अन्य घटनाओं को रोका जाएगा। जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की बाहर आने-जाने में दिक्कत न हो। अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। छात्राओं के स्कूल आने जाने के दौरान भी पुलिस सड़कों पर और विद्यालय के बाहर गश्त करेगी। साथ ही कहा कि शहर में जाम की बढ़ती समस्या से भी निजात दिलाई जाएगी। ऑटो और कैब गैंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

सभी दलों में एक रोग बन गया है

परिवारवाद

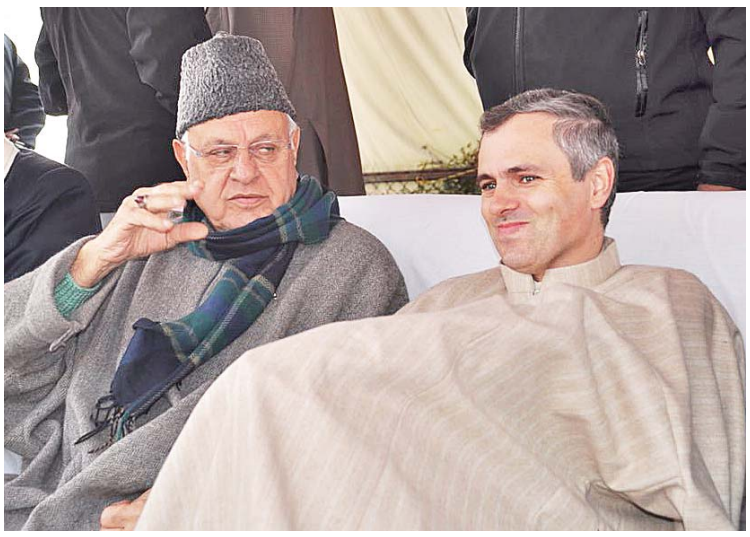

कांग्रेस में नेहरू परिवार का प्रभुत्व था। अतः जो नेता कांग्रेस से विचारों की भिन्नता का बहाना बनाकर अलग हुए, उनके दल परिवार आश्रित हो गये। परिवारवाद के नाम पर नेहरू का विरोध लोहिया ने, इंदिरा गांधी का चरणसिंह ने, चरणसिंह का मुलायम और देवीलाल ने किया; पर आज इन सबके दल निजी दुकान बन कर रहे गये हैं। शरद पवार, उद्धव और राज ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल, ओमप्रकाश चौटाला, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू और मुलायम सिंह यादव, महबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू, स्टालिन, केजरीवाल... आदि केवल नाम नहीं, एक राजनीतिक दल भी हैं।

कुछ दिन पूर्व बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने विधिवत घोषणा की कि उनका भाई आनंद और भतीजा आकाश पार्टी में नंबर दो और तीन के पद पर रहेंगे। कभी कांशीराम और मायावती परिवारवाद के खुले विरोधी थे। फिर बसपा परिवार के दलदल में क्यों कूद पड़ी ? इसका विश्लेषण करें, तो ध्यान में आएगा कि जैसे हर इन्सान को बुढ़ापे में कुछ रोग लगते हैं, ऐसा ही राजनीतिक दलों के साथ भी होता है। परिवारवाद ऐसा ही एक रोग है। भारतीय राजनीति में यह नयी बात नहीं है। असल में राजनीतिक दलों में भिन्नता विचारों के आधार पर होती है। किसी समय कांग्रेस आजादी के लिए संघर्ष करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था थी। उसके मंच पर सब विचारों के लोग आते थे। इसीलिए आजादी मिलने पर गांधीजी ने कांग्रेस भंग करने को कहा था, जिससे लोग अपने विचारों के अनुसार राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ें; पर जवाहर लाल नेहरू उनकी यह विरासत छोड़ने को राजी नहीं हुए।

1947 तक कांग्रेस और उसमें शामिल समूहों का लक्ष्य आजादी था। अतः देश की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक स्थिति; खेती और उद्योग आदि के बारे में उनके विचार किसी को पता नहीं थे; पर आजादी के बाद इन पर अपने विचार बताने जरूरी थे। नेहरू ने वामपंथी रुझान वाले विचार अपनाए और मृत्युपर्यन्त राज करते रहे। आगे चलकर कांग्रेस से डॉ. लोहिया, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेन्द्र देव आदि कई नेता अलग हुए, जिन्होंने मुख्यतः समाजवाद के नाम पर नये दल बनाये। कुछ राज्यों में ये प्रभावी भी हुए; पर इनकी देशव्यापी पहचान नहीं बनी। दूसरी और राष्ट्रवाद तथा हिन्दुत्व के पक्षधर 'भारतीय जनसंघ' के विस्तार का आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। संघ के विस्तार के साथ ही जनसंघ भी बढ़ता रहा। पर धीरे-धीरे राजनीति में विचारों का महत्व घटने लगा। सोवियत रूस के विघटन से साम्यवाद अप्रासंगिक हो गया। अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ने से सबका ध्यान पूंजीवाद की ओर बढ़ा। चीन ने भी साम्यवाद के खोल में पूंजीवाद अपना लिया। भारत में यद्यपि गरीबों के वोट लेने के लिए कोई दल पूंजीवाद का खुला समर्थन नहीं करता; पर सच ये है अधिकांश दल इसी राह पर चल रहे हैं। विचारों का आधार समाप्त होने पर राजनीतिक दलों ने अपने अस्तित्व के लिए परिवार को आधार बना लिया।

कांग्रेस में नेहरू परिवार का प्रभुत्व था। अतः जो नेता कांग्रेस से विचारों की भिन्नता का बहाना बनाकर अलग हुए, उनके दल परिवार आश्रित हो गये। परिवारवाद के नाम पर नेहरू का विरोध लोहिया ने, इंदिरा गांधी का चरणसिंह ने, चरणसिंह का मुलायम और देवीलाल ने किया; पर आज इन सबके दल निजी दुकान बन कर रहे गये हैं। शरद पवार, उद्धव और राज ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल, ओमप्रकाश चौटाला, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू और मुलायम सिंह यादव, महबूबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू, स्टालिन, केजरीवाल... आदि केवल नाम नहीं, एक राजनीतिक दल भी हैं।

इन राजनीतिक दलों की स्थिति उस गृहस्थ जैसी है, जो वर्षों परिश्रम कर मकान, दुकान, जमीन और जायदाद बनाता है। वह चाहता है कि यह सम्पदा फिर उसके बच्चों को मिले। इसी तरह घरेलू दलों के मुखिया चाहते हैं कि उनके बाद यह राजनीतिक सम्पदा उनके बच्चे संभालें। फिर राजनीति करते हुए कार्यालय, गाड़ियां, बैंक बैलेंस जैसी चल-अचल सम्पत्ति भी बन जाती है। दल का जमीनी अस्तित्व भले ही न हो; पर सम्पत्ति का तो होता ही है। उसे अपने कब्जे में रखने के लिए दल के महत्वपूर्ण पद अपने परिवार में बने रहने जरूरी हैं। लेकिन जैसे परिवार में भाइयों और फिर उनके बच्चों में सम्पत्ति के नाम पर झगड़े होते हैं, ऐसा ही इन घरेलू दलों में भी होता है। उ.प्र. में मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत पर कब्जे के लिए उनके भाई शिवपाल और बेटे अखिलेश में झगड़ा है। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की विरासत के लिए उद्धव और राज ठाकरे में टकराव है। आंध्र में एन.टी. रामराव की विरासत उनके बेटे की बजाय दामाद चंद्रबाबू नायडू ने कब्जा ली। चौटाला परिवार में सिर फुटव्वल का कारण भी यही है। बिहार में लालू के दोनों बेटे और बड़ी बेटी उनके असली वारिस बनना चाहते हैं। फिर राजनीतिक जीवन में नेताओं पर कई आर्थिक और आपराधिक मुकदमे लग जाते हैं। इनमें से कुछ असली होते हैं, तो कुछ नकली। यदि पार्टी का मालिक कोई और बन जाए, तो मुकदमों का खर्चा कहां से आएगा ? जेल हो गयी, तो उनकी रिहाई के लिए धरने-प्रदर्शन कौन करेगा ? इसलिए जैसे भी हो; पर पार्टी का अपनी घरेलू जायदाद बने रहना जरूरी है। सुना है मायावती के पास पार्टी के नाम पर अरबों रु. की चल-अचल सम्पत्ति है। कई मुकदमे भी चल रहे हैं। शरीर भी ढलान पर है। वोटर चाहे कहीं भी जाए; पर पैसा तो अपने पास ही रहना चाहिए। उनके संतान नहीं हैं; पर भाई और भतीजे तो हैं। इसलिए उन्हें ही नंबर दो और तीन के पद दे दिये हैं।

सच तो ये है कि बड़े से बड़े पहलवान को भी बुढ़ापे में रोग घेरते ही हैं। उसे चलने के लिए लाठी और बाल-बच्चों का सहारा लेना ही पड़ता है। यही स्थिति घरेलू राजनीतिक दलों की है। बसपा में भी यही हुआ है। औरों को भले ही इसमें कुछ आश्चर्य लगे; पर राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह एक सामान्य बात है।

- निगम के 100 वार्डों में साफ-सफाई का बुरा हाल
- अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को नहीं है परवाह
- वार्डों में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर, नहीं हुई नालों की सफाई

क्या अपनी रैंकिंग को बचा पाएगा गाजियाबाद नगर निगम?

प्रदीप वर्मा

गाजियाबाद। स्वच्छता के मामले में उत्तर प्रदेश में पहली रैंक लाने वाले गाजियाबाद नगर निगम की स्थिति अब बेहद उलट हो गई है। नगर निगम क्षेत्र में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं और अभी तक नालों की भी सफाई नहीं हो पाई है। सीधे-सीधे कहें कि गाजियाबाद कूड़े के ढ़ेर पर बैठा है तो आतिश्योक्ति नहीं होगी। इससे यह सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या गाजियाबाद अगले सर्वेक्षण के लिए तैयार है या इस बार अधिकारियों की उदासीनता की वजह से गाजियाबाद को फिर से निचले पायदान पर आना पड़ेगा?

आपको बता दें कि 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2018 के बीच सर्वेक्षण कराया गया था। जिसमें गाजियाबाद जिला पूरे उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा था। वार्ड स्वच्छता के मामले में भी नगर निगम के वार्ड 67 संजय नगर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। स्वच्छता सर्वेक्षण में मुख्य रूप से जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी और तत्कालीन नगर आयुक्त चंद्र प्रकाश सिंह की अहम भूमिका रही। जिन्होंने अथक प्रयास करके गाजियाबाद को नंबर वन बनाने का काम किया। लेकिन फिलहाल गाजियाबाद की जो स्थिति चल रही है, उससे नहीं लगता कि इस बार गाजियाबाद स्वच्छता सर्वेक्षण में हिस्सा भी ले पाएगा।

गाजियाबाद की मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती कूड़ा डंप करने को लेकर है। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के 100 वार्डों से प्रतिदिन 1800 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। लेकिन नगर निगम अब तक इसके निस्तारण का कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाया है। हालांकि नगर निगम ने कूड़ा डंप करने के लिए गाजियाबाद में कई जगह पर जमीन लीज पर ली हैं, लेकिन इन जगहों पर भी कूड़ा डंप करने को लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। जिसके चलते नगर निगम के सामने कूड़ा डंप करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

दूसरी बड़ी समस्या नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर है जितनी शिद्दत से सर्वेक्षण के समय पर अधिकारी और कर्मचारी साफ सफाई के कार्य में लगे हुए थे उसके उलट अब वार्डों में स्वच्छता कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा नाले भी गंदगी से अटे पड़े हैं। ऐसे में मानसून सिर पर है और थोड़ी सी बारिश भी नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है।

ऐसी स्थिति में साफ है कि नगर निगम को अगले सर्वेक्षण में मुंह की खानी पड़ सकती है और अगर अधिकारियों को इस जिल्लत से बचना है तो स्वच्छता के प्रति उन्हें गंभीर होना पड़ेगा और पूर्व की तरह साफ सफाई की मॉनिटरिंग प्रतिदिन अधिकारियों को खुद करनी होगी। तभी जाकर गाजियाबाद नगर निगम अपनी स्थिति पर बना रह सकता है।

खरबों रुपए की सरकारी जमीन को प्रशासन की कार्यवाही की आस

5000 वर्ग मीटर जमीन पर भूमाफियाओं ने बसा दी आबादी

विशेष संवाददाता

गाजियाबाद। यूपी बॉर्डर पर नगर निगम की खरबों रुपए की जमीन पर आज एक बड़ी आबादी बस गई है और इस आबादी को बसाने का काम किया है सफेदपोश भू माफियाओं ने। अर्थला झील की तरह ही करीब 5000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा किया और फिर इसे बेचकर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। तमाम शिकायतों के बावजूद सरकारी जमीन को खाली नहीं कराया जा सका। लेकिन अर्थला झील की जमीन को लेकर जिस तरह से जिला प्रशासन काम कर रहा है, उससे अब सरकारी जमीन के खाली कराने की भी उम्मीद जगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन सरकारी जमीन को हजम करने वाले भू माफिया और सफेदपोश नेताओं पर कार्यवाही कर पाएगा? या फिर इस तरह से ही भू माफियाओं के हौसले बुलंद रहेंगे।

आपको बता दें कि यूपी बॉर्डर पर करीब 4 साल पहले चिकम्बरपुर गांव की साढे चार बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इस जमीन को कब्जाने में बसपा के तत्कालीन पार्षद और जोनल चेयरमैन की अहम भूमिका रही। जमीन कब्जाने का यह मामला मीडिया में खूब उछला। लेकिन नगर निगम के अधिकारी आरख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कोई गंभीर पहल नहीं हुई। प्रशासक की इस उदासीनता की वजह से 4 सालों में यह जमीन कई बार बिक गई और आज इस पर एक बड़ी आबादी बसी हुई है। इस जमीन को लेकर कुछ समाजसेवियों ने नगर निगम में शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन निगम के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिसके चलते पुराना कविनगर के रहने वाले वरिष्ठ नागरिक एवं समाजसेवी आर एल गृप्ता में नगर निगम में आरटीआई दाखिल की और जवाब मांगा। लेकिन नगर निगम अफसरों ने आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। जिसकी वजह से गृप्ता को लखनऊ में प्रथम अपील दाखिल करने पड़ी। 20 जुलाई 2014 को दायर की पहली अपील का नतीजा यह निकला कि मजबूरीवश नगर निगम को गृप्ता की आरटीआई का जवाब देना पड़ा। नगर निगम ने माना कि चिकंवरपुर के खसर नंबर 26 और 264 की जमीन नगर निगम की संपत्ति में दर्ज है। नगर निगम ने बताया कि जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार और संपत्ति अधिकारी ने राहिणी सेक्टर-9 निवासी श्रीमती प्रेमवती कैलाश रानी चावला और पीतमपुरा निवासी अशोक चावला को 18 जून 2014 को नोटिस थेजे गए थे। साथ ही प्रशासन की ओर से 24 नवंबर 2014 को नगर निगम की जमीन की पैमाइश के लिए एक राजस्व कमेटी गठित की गई।

जिसमें तत्कालीन नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह, राजस्व निरीक्षक, तत्कालीन लेखपाल गोविंद सिंह, कृष्ण पाल शर्मा, सत्यवीर नगर शामिल रहे। जांच कमेटी ने एक दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी गाजियाबाद को सौंपी। जिसमें उन्होंने बताया कि जमीन के बड़े हिस्से पर आबादी बस गई है और कुछ जमीन रास्ते में आ गई है। जांच टीम ने मोहन नगर जोन के कर अधीक्षक से आबादी में बने भवनों का स्वामित्व दस्तावेज सर्वे कराने की सिफारिश की। कुल मिलाकर जमीन पर अवैध कब्जे की फाइल को जांच की नाम पर बंद कर दिया गया। यानि प्रशासनिक लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए की जमीन भू माफियाओं के हाथ में चली गई और उन्होंने जमीन को बेचकर अपना उल्लू सीधा कर लिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक विनीतकांत पाराशर द्वारा भारद्वाज प्रिंटर्स, शॉप नं. 1, प्रिया सिनेमा मार्केट, मुरादनगर, गाजियाबाद से छपवाकर सैकेंड ए-288 नेहरूनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया। संपादक विनीतकांत पाराशर, RNI: UPHIN/2017/74151 प्रशासनिक कार्यालय : ए-288 नेहरूनगर द्वितीय, गाजियाबाद।